Vidyawarta®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed Pin-431126 (Maharashtra)

Certificate Of Publication

This is to certify that the review board of our research journal accepted the research paper/article titled उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ of Dr./Mr./Miss/Mrs. डॉ. राजेश कुमार सिंह

It is peer reviewed and published in the Issue-50 Vol.- 13 in the month of अप्रैल - जून 2024

Thank you for sending your valuable writing for Vidyawarta Journal

Indexed (IIJIF)

Impact Factor 9.29

Govt.of India, Trade Marks Registry Regd.No.2611690

ISSN-2319 9318

Editor in chief
Dr.Bapu G.Gholap

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

International Multilingual Research Journal

Vidyawarta

Issue-50, Vol-13, April to June 2024
Peer Reviewed International Journal

Editor
Dr.Bapu G. Gholap

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

विद्यावार्ता™

April To June 2024
Issue 50, Vol-13

Date of Publication
01 June 2024

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले
-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Date of Publication
01 June 2024

Vidyawarta™

International Multilingual Research Journal

www. विद्यावार्ता .कॉम

YouTube Channel

Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles,Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Editors and publishers have the right to convert all texts published in Vidyavarta (e.g. CD / DVD / Video / Audio / Edited book / Abstract Etc. and other formats).

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.

Indexed

IMPACT FACTOR 9.29 iijif

Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 2611690

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. • International Multilingual Research Journal • CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

http://www.printingarea.blogspot.com

INDEX

01) Embracing E-Commerce: A Catalyst for Modernizing the....
Dr. Vishal Sharma, Dr. Tarun B. Shrivastava, Anupshahr ||10

02) South Asia's Nationalist Movements: A Catalyst for Regional....
Urvashi Singh, Delhi, India ||13

03) Legal Education in India: Ethical Development and Legal Challenges
Dr. Rajesh Khatwani, Bhilwara, Rajasthan ||22

04) Importance Of Phrasal Verbs In English Writing Skills
Mushfique Abdul Aleem Moosa, Professor Kaneez Fatima ||28

05) IMPACT OF COVID 19 ON WOMEN MIGRANT LABOURERS AND....
Chandan Kumar Barman, Dr. Sumita Sinha, Raiganj, U/D ||35

06) The Impact of Online Betting on Cyber Crime in India: A Study....
ADARSH SINGHAL ||42

07) Study of the aspiration levels of student with high and....
Amar Kumar ||48

08) EMPOWERING MINDS: WOMEN'S EDUCATION IN ANCIENT INDIA
Dr. SHOBHA SINGH, JAIPUR ||51

09) AN ANALYSIS OF WOMEN'S EMPOWERMENT THROUGH....
Dr. Vaibhav Popatrao Kawade, Naigaon Dist. Nanded ||55

10) Study of Fish Bacteria, Viruses & Protozoan Parasites....
Vinay Panwar, Gargi Tyagi, Meerut, U.P. ||59

11) सुप्रीम फिटनेस हब मधील व्यायामपट्टूंवर वजन प्रशिक्षणाचा....
मंगेश भागवत पवार, डॉ. कल्पना झरिकर ||66

12) ग्रंथालयाचे बदलते आधुनिक स्वरुप : एक विश्लेषन
डॉ. वाघमारे राजीव किशनराव, नांदेड ||72

13) मध्ययुगीन काळात भारतातील शिक्षणाचा विकास: एक ऐतिहासिक दृष्टीकोन
प्रा. डॉ. शिवचरण नामदेव धांडे, एकोडी जि. भंडारा ||75

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

14) कृषीक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार
अश्विनकुमार आनंदराव मेश्राम, प्रा. डॉ. रेखा बी. मेश्राम, ब्रम्हपुरी ||80

15) दो अथवा चार वर्ष की अवधि वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुद्दे....
Vani Bhattacharya, Dr. Jyoti Puri, Moradabad ||83

16) साम्प्रदायिकता के चपेट में मातृभूमि प्रेम
जयलक्ष्मी साहु ||87

17) दमोह नगर की मुस्लिम महिलाओं की स्थिती: एक भौगोलिक अध्ययन
डॉ. दुर्गा महोबिया, दमोह ||90

18) उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ
डॉ. राजेश कुमार सिंह, सिंगरामऊ, जौनपुर ||94

19) शिक्षको में तनाव
डॉ. दिपक कुमार, कोडरमा, झारखण्ड ||101

20) १८५७ के संग्राम में मेवाती शूरवीरों का योगदान
डॉ. सुप्रिया चौधरी, रामबाग, जयपुर, राजस्थान ||105

21) शैलेय कृत 'हलफनामा' उपन्यास में विस्थापन का दर्द
डॉ. मुकेश सेमवाल ||111

22) भारत में गरीबी की समस्या एवं समाधान
डॉ. रमण कुमार ठाकुर, जयनगर, मधुबनी ||116

23) राजस्थान में जल प्रबंधन : ऐतिहासिक अध्ययन
राखी मीना, जयपुर ||122

24) मध्यकालीन भारत में पंचायती राज
HANSRAJ, RAJGARH, ALWAR (RAJ) ||127

25) बदलते परिवेश में प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां
डॉ. बबीता कुमारी मंडल, उच्चौठ, मधुबनी ||129

26) बदलते परिवेश में वृद्धजनों की स्थिति – झारखण्ड के संदर्भ में
देवकी कुमारी, डॉ. रश्मि, रामगढ़ ||134

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

27) राजस्थान में शक्ति परम्परा का उदय एवं विकास
मनीषा, जयपुर ||142

28) वैश्वीकरण के सामाजिक — आर्थिक प्रभाव
मल्लूराम मीना, सवाई माधोपुर (राजस्थान) ||147

29) कम्बोडिया में देवभाषा संस्कृत
डॉ. सलिल कुमार पाण्डेय, गोरखपुर (उ.प्र.) ||149

30) परिवार में होने वाले घरेलू हिंसा का बच्चों पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव
प्रीति कुमारी, रांची ||154

31) माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर योग के प्रभाव....
डॉ. विजय कुमार, रामबाबू, बाँसी, सिद्धार्थनगर (उ.प्र.) ||158

32) गरूड़ पुराण में निहित नैतिक मूल्यों का आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य....
डॉ. सन्धया खेडा, पलवल ||163

33) कृष्णा सोबती के उपन्यासों में नारी अस्मिता का सामाजिक संदर्भ
डॉ. अनीता, बरेली ||168

34) वर्तमान परिदृश्य में पारिवारिक संरचना का परिवर्तित स्वरूप : एक विश्लेषण
डॉ. राम लखन महतो, बरारी, कटिहार, बिहार ||174

35) विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता....
डॉ. अमर नाथ, परुइय्या आश्रम, अम्बेडकरनगर, (उ.प्र.) ||178

36) Integration of Raja Yoga in Modern Education with Yoga....
Ankita Sood, Mumbai, Maharashtra ||183

37) Distinctions between public administration and private action
Dr. Ambaraya Shivaraya, Kalaburagi ||193

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

प्रश्नावली

क्र.		सर्वोच्च	उच्च	सामान्य	निम्न	दयनीय	कुल
1.	पर्दा प्रथा	Nil	04	60	29	07	100
2.	समानता का अधिकार	02	03	19	54	22	100
3.	सम्मान व प्रतिष्ठा	01	07	30	35	07	100
4.	सम्पत्ति का अधिकार	02	06	32	51	09	100
5.	सहमति का अधिकार	03	04	33	54	06	100
6.	व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार	Nil	02	28	60	10	100
7.	शिक्षा का अधिकार	02	05	30	57	06	100
8.	विवाह का अधिकार	04	06	34	49	07	100
9.	तलाक का अधिकार	01	03	31	59	06	100
10	संतान उत्पत्ति पर अधिकार	Nil	04	29	59	08	100
11	आत्मनिर्भरता का अधिकार	02	02	31	60	05	100
12	धार्मिक मामलो पर अधिकार	03	01	08	54	37	100

क्र.	आयु श्रेणी	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
1.	२० से २५ वर्ष	18	18%
2.	२५ से ३० वर्ष	25	25%
3.	३० से ३५ वर्ष	24	24%
4.	३५ से ४० वर्ष	19	19%
5.	४० से ४५ वर्ष	14	14%
	कुल	100	100%

❑❑❑

18

उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

डॉ. राजेश कुमार सिंह
असि. प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा संकाय
राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर

स्वतंत्र भारत को १९४७ में ब्रिटिश राज से विरासत में केवल प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियाँ ही नही अपितु ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भी प्राप्त हुई थी। जिसे स्वतन्त्र भारत के प्रशासकों और शिक्षाविदों ने ज्यों–का–त्यों अपना लिया। यह बिडंबना ही थी कि जिस विदेशी शिक्षा और सरकारी तन्त्र के विरूद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसे उसी रूप में अपनाने से स्वतंत्र भारत में अनेक विकृतियाँ पनपती गई। तथापि इन विकृतियों को दूर करने हेतु शिक्षा प्रणाली में सुधार का प्रथम प्रयास महान् शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ०४ नवंम्बर १९४८ में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८–४९) द्वारा किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट एक अद्वितीय दस्तावेज है।

कालान्तर में भारत में शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोगों एवं शिक्षा समितियों का गठन किया गया। जिसमें २३ सितंम्बर १९५२ में तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२–५३) तथा १४ जुलाई १९६४ में तत्कालीन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग (१९६४–६६) सर्वप्रमुख हैं। शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार हेतु गठित कोठारी आयोग की रिपोर्ट एक वृहद, अत्यन्त दूरदृष्टि एंव दूरगामी निहितार्थो से सम्पन्न दस्तावेज है। परन्तु विडम्बना यह है कि शिक्षा सुधार के सुझाव का यह ग्रन्थ

पुस्तकालयों की आलमारियों की शोभा बढ़ाने वाला ग्रन्थ मात्र बनकर रह गया है।

भारत में शिक्षा सुधारो के लिए अब तक जितनी भी संस्थाओं या सगठनों की स्थापना हुई है, यथा—यू०जी०सी०, एन०सी०ई०आर०टी०, एन०सी०टी०ई०, सी०ए०बी०ई० आदि के सुधारात्मक कार्यो ने कोई चमत्कार या सुधार दिखाने के स्थान पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को और दुरूह, दुष्कर व द्रुतिगति से ह्रसोन्मुख ही बनाया है।

संख्यात्मक शैक्षिक विकास तो सर्वत्र दिखाई देता है, किन्तु गुणात्मक विकास की चीख—पुकार एवं करूण—क्रन्दन भारतीय मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है।

उच्च शिक्षा में सुधार का स्वप्न तभी साकार होगा, जब शिक्षक, शिक्षक बने नौकर—चाकर नहीं। हम यह नही कहते कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी शिक्षक वेतन के लिए नौकर या गुलाम बन चुके हैं। उनमें से अनेक ऐसे भी हैं जो वास्तव में शिक्षक एवं आचार्य है। आचार्य वशिष्ठ, संदीपन, चाणक्य, गुरू रामदास व वर्तमान युग में महात्मा गांधी व स्वामी विवेकानन्द इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

जहाँ तक मेरा मानना है कि उच्च शिक्षा में सुधार कोई कानून कोई वेतनमान, कोई औचक निरीक्षण तथा कोई दण्ड—विधान नही कर सकता। बिना चाह, बिना प्रतिबद्धता, केवल वेतनमान व आजिविका के लिए तथाकथित प्रशिक्षित शिक्षको द्वारा सरकारी निर्देश और सहायता के द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार की कल्पना करना मश्गमरीचिका में प्यास बुझाने के समान है।

उच्च शिक्षा : ऐतिहासिक पृठभूमि

मानव का सच्चा विकास और उसका संस्करण शिक्षा के द्वारा होता है। परन्तु किसी भी स्तर की शिक्षा, अंग्रेजी शासन की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे नीचे थी।

भारत में दो शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंग्रेजो का शासन रहा। इस बीच वे केवल अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न रहे। सन् १८३५ में लार्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में अंग्रेजों के शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''वर्तमान में हमारा उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रंग और रक्त में भारतीय हो पर रूचियों, विचारों, नैतिकता एवं बौद्धिकता में अंग्रेज हो।'' (स्रोत:— शार्प, १९२०—८६)

मैकाले ने शिक्षा द्वारा भारतीयों की रूचियों, विचारों, नैतिकता एवं बौद्धिकता को अंग्रेजी बनाने का जो स्पष्ट उद्देश्य रखा था उसमें वह पूर्णता सफल रहा। शिक्षा, विशेषकर उच्चशिक्षा केवल कुछ अभिजात वर्गो तक ही सीमित रखी गई तथा यह तर्क दिया गया कि यह स्वत: छनकर जनमानस तक पहुँच जायेगी।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के वर्तमान दौर में एक बार पुन: हमारी शिक्षा व्यवस्था लार्ड मैकाले (१८३५) तथा लार्ड ऑकलैण्ड (१८३९) के 'छनाई या निस्पन्दन के सिद्धान्त' के करीब पहुॅच गई है। भारत में उच्च शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु सन् १९११ में जमशेद जी टाटा द्वारा ''टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स'' की स्थापना की गयी तथा पं० मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना सन् १९१६ में गयी, डी०के० कर्वे द्वारा सन् १९१८ में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी तथा सन् १९२१ में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गयी। अत: इन संस्थानों को भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के शुभारम्भ की नींव माना जा सकता है।

उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति

उच्च शिक्षा से अभिप्राय सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष, विषद् तथा सूक्ष्मशिक्षा से है। यह शिक्षा उस स्तर का नाम है, जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयो, कम्यूनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रदान की जाती है।

आधुनिक भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम सन् १८५४ में वुड के घोषणापत्र के द्वारा दिया गया। इस घोशणा पत्र में कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाय। (स्रोत:—रिची, १९२२ : ३६६)

इन्ही सुझावों के आधार पर १८५७ में कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय (सन् १९४७) देश में कुल २० विश्वविद्यालय तथा ४९६ महाविद्यालय संचालित थे, जिनमे २ लाख ३७ हजार, ५ सौ, ४६ छात्र नामांकित थे। देश में मौजूदा समय में ६७७ विश्वविद्यालय और इन विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध ३७ हजार २०४ महाविद्यालय है तथा इनमें कुल २ करोड़ ९६ लाख २९ हजार २२ छात्र अध्ययनरत हैं जिनमें लगभग एक करोड़ साठ लाख लड़के तथा एक करोड़ ३० लाख लड़कियाँ है।

उच्च शिक्षा की समस्याएँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि उच्च शिक्षा में तीव्रगामी विकास हुआ है तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में निरन्तर एवं पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होने से उच्च शिक्षा की सुलभता में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन, क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा, छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हुई है? यह एक बड़ा प्रश्न है! शिक्षा के व्यापारीकरण तथा बाजारीकरण के कारण शैक्षिक गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के सम्मुख अनेक समस्याएं उपस्थित हुई है–

छात्र अनुशासनहीनता :– उच्च शिक्षा की सम्भवत: सबसे विकराल समस्या छात्र अनुशासनहीनता की है। यह कहना पूर्णतया युक्तिपूर्ण होगा कि इस समस्या की जननी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। जिसकी छत्रछाया में यह दिन–प्रतिदिन भीमकाय रूप धारण करती चली जा रही है और नित्य नूतन आकृति में प्रकट हो रही है।

Source:-

1- N.K. Sidhanta; the problem of discipline in Indian university, p. 4.

2- Kothari commission report, pp.296-297.

निर्देशन व परामर्श का अभाव :– उच्च शिक्षा संस्थाओं में निर्देशन व परामर्श का पूर्णतया अभाव है। अत: छात्र अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने अभिभावकों के दबाव में या किसी अनुभव हीन व्यक्ति के परामर्श से पाठ्य–विषयों का चयन करते है। इन बातों का पहला दुपरिणाम होता है– परीक्षा में असफलता और दूसरा दुष्परिणाम होता है– जीवन में असफलता।

निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के अभाव के कारण अनेक छात्रों को अपने भावी जीवन में पग–पग पर निराशा एवं निष्फलता के झपेटों का शिकार बनना पड़ता है।

दोषपूर्ण पाठ्यक्रम :– स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का इतना प्रसार हुआ हैं कि वह शिक्षा की समस्त उपलब्ध सीमाओं को पार कर गया है। शिक्षा प्रसार के नाम पर कुछ स्थानों पर कर्मठ समाज–सेवकों तथा कुछ अन्य स्थानों पर धानार्जन के लिए लालायित लोगों ने थोड़ी सी भूमि पर कुछ कमरे खड़े करके उनकों कालेजों की संज्ञा दे रखी है।

वास्तविकता तो यह है कि यद्यपि आज के भारत की आवश्यकताएँ एवं आकांक्षाएँ पराधीन भारत की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सर्वथा भिन्न है, तथापि फिर भी पाठ्यक्रमों में कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नही होता। उनमें अब भी वही घिसे–पीटे विषय है, जो आज से ६७ वर्श पहले थे।

दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली :– भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा–प्रणाली मुख्यता निबन्धात्मक प्रकार की है। चूँकि निबन्धात्मक प्रश्न सम्पूर्ण विषय–वस्तु से सम्बन्धित न होकर, उसके केवल एक अंश से सम्बन्धित होते है। अत: वर्तमान परीक्षा–प्रणाली में वैधता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता का पूर्ण अभाव है। यद्यपि इस भयावह एवं दोशपूर्ण परीक्षा–प्रणाली ने अनेक शिक्षा–आयोगों तथा शिक्षा–समितियों का ध्यान अपनी और बरबस खीचा है तथापि फिर भी इस दिशा में अपेक्षित सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। भारतीय शिक्षा आयोग (१९०२) के शब्दों में– ''यदि हमसे विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में किसी एक बिन्दु पर सुझाव देने के लिए कहा जाए तो यह सुझाव परीक्षाओं के सम्बन्ध होगा।''

Source :-

1- Radhakrishnan Commission Report, pp. 337-38.

2- Kothari Commission Report, pp.648-49.

3- Report of the U.G.C.'s Committee on examination reforms, 1962.

अपव्यय :— हमारे देश में उच्च शिक्षा के स्तर पर अपव्यय की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। "डिग्री कोर्स के प्रथम वर्श में जितने छात्र प्रवेश लेते है, उसमें से ५० प्रतिशत से भी अधिक बी०ए०, बी०काम० और बी०एस०सी० की परीक्षाओं में अनुर्त्तीण होते है। स्नातकोत्तर स्तर पर २० से ३० प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में असफल होते है।''

- Dr. S.N. Mukerji, Education in India Today -Tommorrow, p. 195.

शिक्षा में विशिष्टीकरण :— शिक्षा में विशिष्टीकरण से अभिप्राय छात्रों को विभिन्न विषयों में से किसी विशेष विषय में दक्षता प्रदान करने से है, परन्तु विशिष्टीकरण के विरूद्ध आम शिकायत यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों में शिष्टता, व्यावहारिकता एवं दूरदृष्टिता का अभाव होता है। जबकि ये प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के चरित्र के प्रमुख लक्षण होने चाहिए।

Source: - Times of India, January 19, 1959.

शिक्षा का माध्यम :— शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा के सम्मुख एक अत्यन्त जटिल समस्या उपस्थित कर दी है। चूँकि अंग्रेजी दीर्घकाल से उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा का माध्यम रही है, परन्तु संविधान निर्माताओं नें हिन्दी को संविधान में राजभाशा का दर्जा प्रदान किया है और साथ ही २२ अन्य भारतीय भाशाओं को संविधान के अर्न्तगत मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में देश के प्रशासकों के समक्ष समय—समय पर यह समस्या उत्पन्न हुई है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हिन्दी या फिर कोई अन्य भारतीय भाषा हो।

Source:-

1- Radhakrishnan commission report, p. 138.

2- Kothari Commission Report, p.649.

3- Times of India, July 20, 1967.

अस्तु, मौजूदा समय में उच्च शिक्षा की समस्याएँ दिन—प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। इन समस्याओं में शिक्षकों के चयन में अनियमितता की समस्या सर्वप्रमुख है, जिसके कारण योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता तथा शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। फलतः शिक्षा एक व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, जिसमें प्रबन्ध तंत्र की रूचि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के स्थान पर धनार्जन में अधिक दिखाई पड़ रही है।

उच्च शिक्षा के रोजगारोन्मुखी न होने के कारण शिक्षित स्नातकों एवं परास्नातकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अपेक्षित मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण या तो वे न्यूतनम मजदूरी पर कार्य करने के लिए विवश होते है या फिर उनका अपराधीकरण हो जाता है।

शिक्षा में राजनीति का प्रवेश उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक नकारात्मक पहलु है। उच्च शैक्षिक संस्थानों में योग्य एवं मेधावी छात्र भी अपना शैक्षिक उत्थान करने के बजाय राजनैतिक कैरियर बनाने के चक्कर में राजनेताओं के समर्थक बन जाते है और शैक्षिक संस्थानों का शैक्षिक माहौल बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुल मिलाकर उच्च शिक्षा में छात्रों की बढ़ती संख्या, अपरिपक्व छात्र, तटस्थ एवं हीन गुणता वाले अध्यापक, अपर्याप्त संसाधन, शिक्षा के सभी स्तरों पर अपर्याप्त समन्वय, स्वस्थ्य सम्बद्धन प्रक्रिया तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम व कुशल प्रतियोगियों को तैयार करने की समस्याएँ अब भी बनी हुई है।

उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ

उच्च शिक्षा के समक्ष मुख्य चुनौती कतिपय 'सुविचारित नई रणनीतियों' के बनाने की है। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी नीति तथा कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिसमें एक ही दिशा में निरन्तर आगे बढ़ने की क्षमता हो, जिससे एक ओर जहाँ गुणात्मक उन्नयन साकार हो सकें, वही दूसरी ओर मात्रात्मक विस्तार में भी कमी न आने पाये। तथापि सबके लिए गुणात्मक उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की शीर्श प्राथमिकताओं में होनी चाहिए, जो कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है।

महँगी होती उच्च शिक्षा :— महँगी होती उच्च शिक्षा, भारतीय उच्च शिक्षा के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है। १९९१ के उदारीकरण के पश्चात् उच्च शिक्षा में महँगाई आसमान छू रही है। आसमान छूती महँगाई के बीचे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह व्यक्तव्य आया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उच्च शिक्षा को नई सूचना तकनीकि—उन्मुख बनाने हेतु जिस विशाल धनराशि की आवश्यकता है, उसे जुटा पाना सरकार के सामर्थ्य से बाहर है। अत: अन्य स्त्रोतो से संसाधन जुटाना आवश्यक है।

इस प्रकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानो में विभिन्न प्रकार के शुल्क कई गुना तक बढ़ा दिये गये तथा विविद्यालयों ने भी यू०जी०सी० के निर्देशों का हवाला देते हुए कई विभागों से यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि, वे अपने सम्बन्धित खर्चे स्वयं चलाये। अत: कुछ सीटे छात्रों को बेंच दें या स्ववित्तपोशित पाठ्यक्रम चलायें। इस प्रकार देखते—देखते अनेक मास्टर्स, बैचलर्स और डिप्लोमा कोर्स की डिग्रियाँ व्यवहारिक रूप से बिकने लगीं जिसे समाज के केवल सम्पन्न वर्ग लोग ही खरीदने में सक्षम है। अस्तु, सामान्य जनता को उच्च शिक्षा के लाभों से वंचित करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

निजी क्षेत्र की बढ़ती रूचि :— उदारीकरण की प्रक्रिया से उत्साहित होकर उच्चशिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की रूचि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चूँकि भारत का निजी क्षेत्र उद्योग एवं व्यापार में बहुराष्ट्रीय निगमों से मात खा रहा है। अत: उन्हें लगता है कि उच्च शिक्षा उनके लिए एक सुरक्षित एवं लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है।

तथापि विगत कुछ वर्शो में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उद्योगपतियों एवं शिक्षा माफियाओं का प्रादुर्भाव बहुत तीव्र गति से हुआ है और पूरी शिक्षा—व्यवस्था के समानान्तर एक 'वित्त आधारित डिग्री व्यवस्था' मजबूती से पैर जमाकर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अपनी चमक—दमक एवं आधुनिकता से बौना होने का एहसास कराने लगीं।

परिणामत: सरकारी शिक्षण संस्थाओं ने भी कोचिंग सेन्टरों और प्राइवेट कॉलेजों की तरह वित्तपोशित डिग्रियाँ बेचना प्रारम्भ कर दी है और इन्हें प्रभावी ढंग से रोकने की जगह यू०जी०सी० भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्ववित्तपोशित पाठ्यक्रमों के माध्यम से कोचिंग सेन्टरों एवं प्राइवेट कॉलेजों की तरह शिक्षा के व्यापार में अधिक—से—अधिक लाभ प्राप्त करने वाले प्रतिद्वन्दी के रूप में उतारने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं।

पिछले एक दो दशकों में शिक्षा का जिस तरह व्यवसायीकरण हुआ है उसने देश के तमाम उद्योगपतियों को रातोंरात शिक्षाविदों के रूप में रूपान्तरित कर दिया है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा पूँजी उद्योग में बदलता चला जा रहा है और मुनाफा मुख्य उद्देश्य बन गया है।

विश्वविद्यालय स्वायत्तता :— ज्ञान, मूल्य एवं कौशल का संरक्षण तथा उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार का दायित्व विश्वविद्यालयों का है और इन दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए स्वायत्तता एक अनिवार्य शर्त है।

स्वायात्तता का अर्थ केवल कुलपति या संकायाध्यक्ष को अधिक अधिकार सम्पन्न बना देना ही नहीं है। बल्कि स्वायत्तता से तात्पर्य स्वतन्त्रता एवं दायित्वबोध से है।

जबकि सरकार भविश्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने की योजना बनाई जा रही है तथापि सरकार के इस कदम ने एक साथ कई प्रश्न खड़े कर दियें है—पहला, काउन्सिल के माध्यम से जिस तरह सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रही है। उससे विश्वविद्यालय की स्वायत्ता खतरे में पड़ गयी है। दूसरा, काउन्सिल के सदस्यों की योग्यता एवं इमानदारी सन्देह से परे नहीं है। तीसरा, अगर सुविधा प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अधिक अनुदान दिया जाने लगा तथा अपेक्षाकृत कमजोर शिक्षण संस्थाओं को अनुदान से वंचित किया जाने लगा तो, भविष्य में इन उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच की खाई पटने की जगह और भी बढ़ती जायेगी जिससे सामाजिक विषमता के साथ—साथ शैक्षिक विशमता भी बढ़ेगी।

नव—उपनिवेषवाद एवं उच्च शिक्षा :— उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में उच्च शिक्षा,

नव–उपनिवेशवाद के रूप में एक गम्भीर चुनौती का सामना कर रही है। विगत कुछ वर्शो में भारत आने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। विदेशी विश्वविद्यालय, देशी एजेन्टों तथा सस्थाओं के साथ मिलकर महँगें पाठ्यक्रम संचालित करके अपने धनार्जन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह से करने में सफल होते है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में 'ट्विनिंग' कहा जाता है।

नव–उपनिवेषवाद की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारतीय विद्धानों, अध्यापकों एवं शोधकर्ताओं में हीन भावना लगातार बढ़ती जा रही है। वे किसी पश्चिमी विश्वविद्यालय में पहुँचकर, किसी गोरे विद्वान् के अधीन कार्य कर अपनी विद्वता और श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास करते है और हमारे विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान उनकी श्रेष्ठता को बिना किसी प्रश्न चिन्ह के स्वीकार भी कर लेती है। इस प्रकार पश्चिमी जगत को अपना बौद्धिक नेतृत्व सौप कर हम आत्ममुग्ध हो जाते है।

अस्तु, वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की सर्वप्रमुख चुनौती है– सभी राज्यों में एक समान शिक्षा नीति का न होना, हलाँकि शिक्षा को समवर्ती सूची (अनु०–२५) के अन्तर्गत रखा गया है तथापि फिर भी राज्यों पर कोई भी पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा थोपा नहीं जा सकता। परन्तु, परस्पर समन्वय स्थपित कर एक सम्यक्, समावेशी, सुदश्ढ़, समग्र और सन्तुलित पाठ्यक्रम का ढाँचा सामने रखा जा सकता है। सच्चे युगद्रष्टा डॉ० लोहिया ने सटीक कहा था–

राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान
बिड़ला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान।

यदि हम इस दूरदर्शी नीति को लागू करते है और राष्ट्र निर्माता कहें जाने वाले अध्यापक, जागरूक अभिभावक व जिज्ञासु विद्यार्थी आपसी समन्वय का प्रण करते है, तो इस विकासशील देश को २०२० तक डॉ० कलाम के सपनों के अनुरूप नवशक्त और विकसित मानव संसाधनयुक्त भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता।

निष्कर्ष :– भारत में औपनिवेषिक काल में उच्च शिक्षा की नींव कमजोर आधारशिला पर रखी गयी। स्वतन्त्र भारत में राधाकृष्णन् आयोग (१९४८–४९) ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उच्च शिक्षा की भूमिका को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हुए इसका दायित्व सरकार को सौपा, किन्तु सरकार अपनी भूमिका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम करती जा रही है तथा भविश्य में वह इस क्षेत्र से पूरी तरह निकलने की योजना बना रही है।

उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन (१९५३) हुआ तो जरूर पर आज कुलपति का दायित्व संभाल रहा व्यक्ति भी अपने पद की गरिमा के साथ न्याय नहीं करता है। अगर स्थिति यही रही तो विश्वविद्यालय जैसी स्वायत्त संस्था की विश्वसनीयता संदेहास्पद होती चली जायेगी।

जब पूरी दुनिया ने विद्यालय की भी कल्पना नहीं की थी, उस वक्त हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्वस्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पावन धरती पर शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियाँ कहीं–न–कहीं बहुत कचोटती है। शिक्षा में जब सियासत की गैर जरूरी घटिया दखलंदाजी बढ़ती है, तो बेवजह शिक्षा–जगत को शर्मसार होना पड़ता है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है–

सियासतदानों को हम आदमी समझें तो क्यों समझे
सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती।

उच्च शिक्षा पर बहस तब बेमतलब लगने लगती है, जब यह तथ्य जेहन में उभरता है कि तीन साल पहले बिहार के विश्वविद्यालयों में एक ही जाति के छह कुलपति नियुक्त थे और इसके पीछे की कहानी सबको मालूम है। कुछ साल पहले पांडिचेरी के शिक्षा मंत्री के स्थान पर कोई अन्य विद्यार्थी उनके लिए माध्यमिक की परीक्षा दे रहा था। ऐसे में उच्च शिक्षा में सुधार की संभावना को आघात लगता है।

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, प्रो० यशपाल समिति का गठन हुआ, रिपोर्टें भी आयी। १९८६ में रोजगारोन्मुखी नयी शिक्षा नीति भी लायी गयी, पर आज भी हम एक अदद

मूल्यपरक शिक्षा–नीति की बाट जोह रहे है।

शिक्षा के वैश्वीकरण के इस दौर में महँगे कोचिंग संस्थान, किताबों की बढ़ती कीमत, डीम्ड विश्वविद्यालय और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम धारणा का पनपना आज की तारीख की अहम उच्च शैक्षिक चुनौतियाँ है।

उर्दू कविता के एलेक्जेंडर पोप कहे जाने वाले अकबर इलाहाबादी ने इस स्थिति को भाँपते हुए कहा था–

न पढ़ते तो खाते सौ तरह कमा कर
मारे गये हाय तालीम पाकर
न खेतों में रेहट चलाने के काबिल
न बाजार में माल ढ़ोने के काबिल।

अस्तु, हमें गुणात्मक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें नैतिकता का पुट हो। इस उपभोक्तावादी संस्कृति नें हमें 'स्व' से अलग कर दिया है। खुद से संवाद की संभावना का लोप हो गया है और बाजार–निर्देशित–नियंत्रित–केन्द्रित व्यवस्था नें शिक्षा को सबसे ज्यादा लपेटा है। इस शिक्षा पद्धति का जिस्म तो बुलंद है, पर रूह नासाज़ हो चली है।

इस रूग्णात्मा की तामीरदारी के ठोस हल जल्द ढूंढने होगे। युवा पीढ़ी के अन्दर की बैचेनी व छटपटाहट को समझते–परखते हुए उसे भटकाव से रोकना होगा। मस्तिष्क, हृदय और हाथ के सुन्दर समन्वय से मुकम्मल शख्सियत के निर्माण की प्रक्रिया का द्वार खोलना होगा।

भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी के कारण लगभग ८० हजार युवा प्रतिवर्ष विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ७ अरब डालर यानी ४३ हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च करने पड़ते है। वही भारत में बाहर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष के हिसाब से केवल आठ हजार का औसत रखती है। वेसे भी इसमें अधिकांश भारतीय मूल के ही होते है।

इस बीच यह चर्चा जोरों पर थी कि विदेशी विश्वविद्यालयो को देश में आने और पैर पसारने की अनुमति देने से यहाँ की उच्च शिक्षा स्तर में कुछ सुधार हो। इस सन्दर्भ में मेरा मानना है कि, यदि ज्ञान–विज्ञान के प्रसार व विनिमय हेतु कोई विदेशी विश्वविद्यालय भारत आना चाहें, तो अलग बात है, आखिर उसका नाम ही विश्वविद्यालय है। लेकिन यदि इसका मकसद महज मुनाफा कमाना है, तो फिर यह न सिर्फ अशुभ संकेत हैं, बल्कि घोर आपत्तिजनक भी है।

सही मायनों में हमें आज राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के ढ़ाँचे को वैश्विक रूप प्रदान करने की महती आवश्यकता है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए उनमें ढाँचागत सुधार, शोध गुणवत्ता, शिक्षक–छात्र अनुपात व मानकों के अनुरूप शिक्षकों की अबिलम्ब नियुक्ति जैसे संवेदनशील मुद्दो पर गम्भीरता से विचार करके व त्वरित कार्यवाही करके उच्च शिक्षा की छवि को सुधारा जा सकता है तथा साथ ही भारत को फिर से विश्व गुरू की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है।

चयनित संदर्भ ग्रन्थ–सूची

१. अग्रवाल, उमेश चन्द्र; निजीकरण की ओर अग्रसर उच्चशिक्षा, योजना, सितम्बर–१९९९।

२. कोठारी, डी०एस० (१९७०) एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेंट' (रिपोर्ट ऑफ द एजूकेशन कमीशन, १९६४–६६) भाग–३, नई दिल्ली : एन०सी०ई०आर०टी।

३. गुप्ता, एस०पी० (२०१५) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, पृ० ३४२।

४. त्यागी, गुरसरनदास (२०१२) भारत में शिक्षा का विकास, पृ० ३५५–५६।

५. शरीफ, अबुल सलेह; ब्रिटिश भारत और आजाद भारत में मानव विकास, योजना, अगस्त–२००७, पृ० ४८।

६. शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य, १९८५।

7- Indian Journal of Education Research, Vol-27, No-02, July-December, 2008.

8- New National Policy on Education, 1986.

9- Nurullah & Naik : History of Education in India, p. 278

10- Srimali, K.L. 1961 Problems of Education in India, New Delhi.

11- Statistics on Indian Higher Education, 2014-15.

12- Sudhanshu bhushan : A Neo Liberal Ajenda of Knowledge Commission(University News, Vol 45, 110-25, June 18-24, 2007, p.5.

13- University News, Vol 50, No 40, Oct 01-07, 2012.